प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 22.05.2017

श्री रणदीपसिंह सुरजेवाला, मीडिया प्रभारी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस; श्री अविनाश पांडे, महासचिव, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री सचिन पायलट, अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस; श्री रामेश्वर डूडी, नेता विपक्ष, राजस्थान द्वारा आज निम्नलिखित बयान जारी किया गया :–

(1) खेती किसानी के लिए अभिशाप– भाजपा सरकार के तीन साल

केन्द्र और राज्य की भाजपा सरकारों ने किसानों के साथ धोखा किया है । धरती पुत्र किसानों के हकों पर कुठाराघात कर किसानों को आत्महत्या की ड्योढी पर धकेल दिया । अनाज माफिया तथा जमाखोरों की बलिवेदी पर किसानों की आहुति देना ही असली मायने में भाजपा सरकारों का चाल चरित्र व चेहरा बन गया है ।

(2) भाजपा सरकार में समर्थन मूल्य से वंचित किसान

भाजपा सरकार ने अपने घोषणा पत्र के पृष्ठ क्र. 44 में यह वादा किया था कि वह किसानों को उनकी लागत + 50% मुनाफा समर्थन मूल्य के रूप में देगी, जिसे उसने 20 फरवरी 2015 को सुप्रीम कोर्ट में शपथपत्र देकर नकार दिया । बाद में किसानों से एक और झूठा वादा किया कि 2022 तक फसलों के दाम दुगने कर दिये जावेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि न तो किसानों को बाजार में फसलों के दाम मिल रहे हैं, न ही भाजपा सरकार किसानों से पर्याप्त मात्रा में समर्थन मूल्य पर अनाज खरीद रही है।

एग्रीकल्चर सेंसेस के अनुसार देश में कुल 13 करोड़ 83 लाख किसान हैं और राजस्थान में 68 लाख 88 हजार किसान रहते हैं, जिसमें से 25 लाख किसान सीमान्त हैं और 15 लाख छोटे किसान हैं । राजस्थान सरकार किसानों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है। न तो किसानों से समर्थन मूल्य पर पर्याप्त अनाज खरीदा जा रहा है, न ही बाजार में फसलों के दाम मिल पा रहे हैं।

नीचे दिए गए चार्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि राजस्थान की प्रमुख फसलों का उत्पादन 2016–17 में कितना था और समर्थन मूल्य पर कितना अनाज खरीदा जा रहा है ।

वर्ष 2016–17 उत्पादन लाख टन में

वर्ष 2016–17	धान	गेहू	मोटा अनाज
उत्पादन	4.52	110.04	181.07

समर्थन मूल्य पर खरीदा गया धान, गेहूँ और मोटा अनाज (लाख टन में)

	2014-15			2015-16			2016-17		
	धान	गेहूं	मोटा अनाज	धान	गेहूं	मोटा अनाज	धान	गेहूं	मोटा अनाज
राजस्थान सरकार	0	21.59	0	0	13	0	0	7.62	0
भारत सरकार	**320.40**	**280.23**	**4.65**	**342.18**	**280.88**	**2.60**	**304.35**	**229.62**	**0.72**

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि राजस्थान में 2016–17 में 110.04 लाख टन गेहूँ के उत्पादन पर राजस्थान भाजपा सरकार किसानों से मात्र 7.62 लाख टन गेहूँ समर्थन मूल्य पर खरीदती है । इतना ही नहीं पिछले तीन वर्षों में राजस्थान सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूँ की खरीद तीन गुना कम कर दी है । वहीं केन्द्र की भाजपा सरकार भी किसानों से बीते तीन वर्षों से लगातार गेहूँ, धान व मोटे अनाज की समर्थन मूल्य पर खरीदी कम करती जा रही है ।

(3) प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना– निजी कम्पनियों को लाभ पहुँचाने की साजिश

1 अप्रेल 2016 से मोदी सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना को लेकर मोदी सरकार निरंतर यह प्रचार कर रही है कि यह विश्व की सर्वाधिक उत्कृष्ट बीमा योजना है।

1 अप्रेल 2016 से लागू की गई मोदी सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में यह प्रावधान किया गया है कि वास्तविक प्रीमियम को आधार बनाकर किसानों को प्रीमियम पर सब्सीडी दी जाएगी । अर्थात रबी और खरीफ के लिए 1.5 प्रतिशत और 2 प्रतिशत की दर से बीमित राशि का प्रीमियम देना होगा और कमर्शियल क्रॉप के लिए 5 प्रतिशत की दर से देना होगा और बाकी प्रीमियम की राशि का भुगतान केन्द्र सरकार और राज्य सरकार 50–50 प्रतिशत के आधार पर वहन करेगी । फिर वह राशि बीमा कम्पनियों के खाते में डाल दी जावेगी। मोदी सरकार ने लगभग 10 से अधिक निजी कम्पनियों को इस योजना के लिए इमपेनल्ड किया है जिनमें रिलायन्स जनरल इंश्योरेंस

कम्पनी लि., टाटा ए.आय.जी. एच.डी.एफ.सी. बजाज अलायन्स, आय.सी.आय.सी.आय. कम्पनी इत्यादि। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी को नोडल एजेन्सी बनाया गया है।

खरीफ 2016

बीमित किसान की संख्या	प्रीमियम की राशि	किसानों का मुआवजा	निजी कम्पनियों का शुद्ध लाभ
3 करोड़ 90 लाख	**17184** करोड रु	**6808.48** करोड रु	**10376.31** करोड रु

नोट – **अनुमानित खरीफ और रबी का कम्पनियों को लाभ 20 हजार करोड़ रुपए ।**

कृषि मंत्रालय ने बताया कि वर्तमान में खरीफ 2016 के मुआवजे का पूरा मूल्यांकन कर लिया गया है और अन्ततः 5251143 किसानों को 6808.48 करोड़ मुआवजा प्रदान किया जाना है ।

(4) भाजपा सरकार में – 35 किसान रोज आत्महत्या को मजबूर

केन्द्र की भाजपा सरकार के उपेक्षित रवैये से किसान लगातार हताश होता जा रहा है । न ही उसे बाजार में फसलों के दाम मिल रहे हैं, न ही पर्याप्त मात्रा में समर्थन मूल्य पर उसका अनाज भाजपा सरकार खरीद रही है । लगातार तीन वर्षों से देश में किसानों की आत्महत्या की दर बढ़ती जा रही है । सबसे ज्यादा आत्महत्या सीमान्त और छोटा किसान कर रहा है ।

Year	Farmers/Cultivators	Agricultural Labourers	Total
2014	5650	6710	12360
2015	8007	4595	12602
2016	विशेषज्ञों के आकलन के अनुसार		14000

(5) भाजपा सरकारों की बेरुखी और कर्ज में डूबा किसान
राजस्थान के किसानों का कर्जा क्यों नहीं होता माफ

आज देश का किसान गम्भीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है । वह अपेक्षा कर रहा है कि भाजपा सरकार उसके कर्ज की राष्ट्रव्यापी माफी करे, क्योंकि मोदीजी ने अपने मुट्ठी भर मित्रों के 1 लाख 54 हजार करोड़ रुपए के कर्ज को बीते तीन सालों में माफ कर दिया है ।

2015–16 में राजस्थान में किसानों पर को–ऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक एवं कॉमर्शियल बैंकों का क्रॉप लोन 56902 करोड़ रुपए और टर्म लोन 10724 करोड़ अर्थात् कुल 67627 करोड़ रु. का कर्ज किसानों पर था । क्या राजस्थान सरकार ने स्वयं या केन्द्र सरकार से किसानों की कर्ज माफी की इच्छा जताई ?

(6) सूखा राहत के नाम पर किसानों से भाजपा का छलावा

देश के कई राज्य बीते तीन वर्षों से सूखे की गिरफ्त में हैं, मगर केन्द्र सरकार के नकारात्मक रवैये से किसान हताश हैं । हमने देखा कि तमिलनाडु के किसानों ने कई दिनों तक जन्तर मन्तर पर धरना दिया, भूख हड़ताल की और विभिन्न प्रकार से केन्द्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया, मगर फिर भी बी.जे.पी. की सरकार ने किसानों की पीड़ा को सुनना भी उचित नहीं समझा । इसी प्रकार **राजस्थान सरकार को मोदी सरकार ने 2015–16 के सूखे की 10537 करोड़ रु. की माँग पर मात्र 1193 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए । यह भाजपा सरकारों की राजस्थान के किसान के प्रति उदासीनता का सबसे पुख्ता सबूत है।**

(7) गेहूँ का घोटाला

2013–14 में कांग्रेस सरकार ने 55 लाख टन गेहूँ का निर्यात किया, जिससे देश व किसानों को 9300 करोड़ रु. का फायदा हुआ। भाजपा सरकार के आते ही गेहूँ निर्यात की बजाए चंद जमाखोरों व गेहूँ के आयातकों को फायदा देने के लिए कांग्रेस द्वारा गेहूँ के आयात पर लगाया टैक्स 25% से घटाकर 0% कर दिया गया। नतीजा यह है कि अकेले जनवरी 2017 तक (जैसे ही किसान का गेहूँ बाजार में आने वाला था) 30 लाख टन गेहूँ (लागत 4400 करोड़ रु.) विदेशों से मंगवा लिया गया और 20 लाख टन गेहूँ और मंगवाने की तैयारी है। ऐसा क्यों? क्या यह गेहूँ आयातकों को फायदा पहुंचाने और किसान को दर्द देने का सीधा रास्ता नहीं?

Wheat Export

Product	2013-14	
	Qty. (Lakh Tonne)	Rs. Crore
Wheat	55.62	9261.60

Wheat Import In Lakh Tonnes

April 2015 - September 2015		April 2016 - January 17	
Quantity (Lakh Tonnne)	Value (Crore)	Quantity (Lakh Tonnne)	Value (Crore)
4.29	721.77	30.28	4375

(8) भाजपा सरकार गला रही है दाल माफियाओं की दाल

देश को लगभग 23 मिलियन टन दाल की आवश्यकता होती है। हमने देखा कि बीते वर्षों मोदी सरकार ने दाल माफियाओं के साथ मिलकर 44 रुपए प्रतिकिलो की आयात की हुई दाल के कृत्रिम रूप से भाव बढ़ाकर 230 रुपए तक देश में बेची और 2 लाख करोड़ से अधिक का घोटाला किया । इस बार भी मोदी सरकार नए तरीके से दाल माफियाओं के साथ मिलकर किसानों को आघात पहुँचा रही है । इस बार दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार दाल का उत्पादन 2016–17 में 221 लाख टन आँका गया है, मगर केन्द्र सरकार ने दाल माफियाओं को 10 प्रतिशत इम्पोर्ट ड्यूटी के साथ दाल आयात की खुली छूट दी और दाल का आयात 2016–17 में 54.20 लाख टन कर लिया गया । अब परिस्थितियाँ यह निर्मित हो रही हैं कि किसानों को दाल के भाव बाजार में नहीं मिल रहे हैं और न ही केन्द्र सरकार पर्याप्त मात्रा में समर्थन मूल्य पर दाल खरीद रही है। भाजपाशासित राज्यों के मुख्यमंत्री ही केन्द्र सरकार के इस कदम के खिलाफ उँगलियाँ उठा रहे हैं ।

Pulse Production

In Lakh Tonnes

	2014-15	2015-16	2016-17
	Quantity	Quantity	Quantity
Production	171.5	163.5	221.4
Demand	226.8	230	230

Pulse Import

2014-15		2015-16		2016-17	
Quantity (Lakh Tonne)	Rate /kg Rs.	Quantity (Lakh Tonnne)	Rate /kg Rs.	Quantity (Lakh Tonne)	Rate /kg Rs.
45.84	37.22	57.97	44.19	54.20	43.44

(9) मोदीजी ने देश के गरीब परिवारों के मुँह में कड़वाहट घोल दी

देश के 30 राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत असमर्थ परिवारों को शक्कर की प्रतिपूर्ति के लिए राज्यों को 18 रु. 50 पैसे प्रति किलो के हिसाब से केन्द्र द्वारा दिया जाता था और राज्य सरकारें 13 रु. 50 पैसे प्रति किलो में शक्कर उपलब्ध कराती थी, मगर मोदी जी ने 1 अप्रेल 2017 से देश के गरीबों के मुँह से मिठास छीन ली और केन्द्र सरकार की ओर से दिये जा रहे 4,500 करोड़ रु. राज्यों को बन्द कर दिए । इस बड़े कुठाराघात पर वसुन्धरा सरकार ने राज्य के गरीबों के पक्ष में आवाज तक नहीं उठाई ।